दिल्ली नगर निगम

बनाम

अजंता आयरन एंड स्टील कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड।

28 फरवरी, 1990

[ललित मोहन शर्मा, न्यायाधीश और वी. रामास्वामी, न्यायाधीश]

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910: बिजली आपूर्ति-का विच्छेदन-नोटिस देना एक पूर्व आवश्यकता है। दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम ने उपभोक्ता को नोटिस दिए बिना निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी-कंपनी को बिजली की आपूर्ति काट दी। निचली अदालत ने आपूर्ति बहाल करने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए संशोधित मुकदमे को खारिज कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा बिजली की आपूर्ति के संबंध में शर्त संख्या 36 के तहत आवश्यक नोटिस की तामील न करने के एकमात्र आधार पर वाद का फैसला सुनाया। उसने वादी द्वारा बिजली की चोरी के आरोप पर विचार नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

विशेष अनुमति द्वारा अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. अनुज्ञप्तिधारी उपक्रम एक सार्वजनिक कर्तव्य का पालन कर रहा है और एक विशेष क़ानून द्वारा शासित है। कानून में यह भी है कि बिजली की आपूर्ति काट देने से पहले एक सूचना दी जाये। अपीलार्थी को अपने शब्दों से पीछे हटने और उपभोक्ता को समझौते द्वारा दिये गए नोटिस के लाभ से इनकार करने की भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वाद पर सही निर्णय दिया गया था। [735 बी-सी, ए-बी]

2. वादी चोरी के आरोप को गंभीरता से नकार रहा है। इस मुद्दे पर पूर्ण परीक्षण के बिना आरोप को सही मान लेना संभव नहीं है। नीचे की अदालतों ने गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच नहीं की है। यह सवाल कि क्या आरोप सही हैं या नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए और उचित कार्यवाही में निर्णय लिया जाना चाहिए। इसलिए, अपील के खारिज होने से अपीलार्थी के दावे में पूर्वाग्रह नहीं होगा।

[734 जी-एच, 735 सी]

जगरनाथ सिंह बनाम बी. एस. रामास्वामी, [1966] 1 एस. सी. आर. 885, विशिष्ट।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 3693/1989

(आर. एस. ए. सं. 31/1989 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 23.2.1989 से।)

के. एस. बिंद्रा, आर. के. माहेश्वरी और जी. एस. गुजनानिप अपीलार्थी कि ओर से ।

प्रतिवादी के लिए प्रेम सुंदर झा।

न्यायालय का निर्णय श्री शर्मा, न्यायाधीश द्वारा दिया गया।

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील एक मुकदमे से उत्पन्न होती है जो प्रतिवादी -कंपनी द्वारा अपीलार्थी, दिल्ली नगर निगम के खिलाफ मुकदमा लंबित रहने के दौरान बंद की गई बिजली की आपूर्ति को बहाल करने के लिए एक अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया था। शुरू में मुकदमा बिजली कनेक्शन काटने पर निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया था। बिजली की आपूर्ति बंद होने के बाद शिकायत में संशोधन किया गया था।

2. वादी के मामले के अनुसार, मुकदमा दायर करना पड़ा क्योंकि दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम बिना किसी कारण का खुलासा किए कनेक्शन काटने की धमकी दे रहा था। इसके बाद, उपक्रम के कुछ अधिकारियों ने मीटरों का निरीक्षण किया और मीटरों पर लगी मुहरों के साथ छेड़छाड़ करने के बाद बिजली की चोरी का आरोप लगाया। पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

3. स्वीकार्य रूप से दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम ने बिजली काटने से पहले वादी को कोई नोटिस नहीं दिया था। हालाँकि, विद्वत निचली अदालत ने मुकदमे को खारिज कर दिया और वादी ने अपील की। दिल्ली के प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जिन्होंने अपील की सुनवाई की, ने नोटिस की तामील न करने के एकमात्र आधार पर मुकदमे का फैसला सुनाया, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा बिजली की आपूर्ति के संबंध में शर्त सं-36 के तहत आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक तर्कपूर्ण निर्णय द्वारा अपीलार्थी की दूसरी अपील को स्वीकार करने के चरण में खारिज कर दिया।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि बिजली की चोरी में वादी के आचरण को देखते हुए, न्यायालय को अपने विवेक से बिजली की आपूर्ति की बहाली के लिए निर्देश जारी करने से इनकार करना चाहिए। क्षमा चाहते हैं कि हमारे लिए एक से अधिक कारणों से अपीलार्थी से सहमत होना संभव नहीं है। वादी चोरी के आरोप को गंभीरता से नकार रहा है और इस मुद्दे पर पूर्ण परीक्षण के बिना आरोप को सही मान लेना संभव नहीं है। जगरनाथ सिंह बनाम बी. एस. रामास्वामी, [1966] 1 एससीआर 885 का मामला; जिस पर अपीलार्थी की ओर से भरोसा किया गया है को स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता है क्योंकि उस मामले में उपभोक्ता को भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया था और अपील में दोषसिद्धि बनाए रखी गई थी। इसके अलावा, नोटिस की तामील कनैक्शन काटने के लिए एक पूर्व शर्त है, और अपीलार्थी को

अपने शब्दों पर वापस जाने और उपभोक्ता को समझौते मे दिये गए नोटिस के लाभ से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि यदि इस विचार को बरकरार रखा जाता है तो दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम को गंभीर रूप से नुकसान होगा। हम यह नहीं समझते हैं कि आपूर्ति बंद करने से पहले उपभोक्ता को नोटिस देने में अपीलार्थी के रास्ते में क्या कठिनाई है। यह समझना चाहिए कि अनुज्ञप्तिधारी उपक्रम एक सार्वजनिक कर्तव्य का पालन कर रहा है और एक विशेष क़ानून द्वारा शासित है और कानून में भी बिजली की आपूर्ति को काटने से पहले एक नोटिस देने का प्रावधान है। निचली अदालतों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच नहीं की है। यह प्रश्न कि चोरी के आरोप सही हैं या नहीं, की जांच की जानी चाहिए और उचित कार्यवाही में निर्णय लिया जाना चाहिए, और इसलिए, वर्तमान निर्णय से अपीलार्थी के दावे में पूर्वाग्रह नहीं होगा। परिणामस्वरूप, अपील खारिज कर दी जाती है, लेकिन बिना किसी हर्जे खर्चे के।

पी. एस.

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।